



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 मई, 2003/3 ज्येष्ठ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2003

संख्या एल०एल०आर०डी० (6)-6/2003-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-6-2003 को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

## हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003

भारत गणराज्य के जीवनवै वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित :

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003 है । संक्षिप्त नाम

(1994 का 13). 2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन ।

(i) उप-धारा (3) में,—

(क) “और राज्य सरकार, अधिमूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी.”, शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “1” चिन्ह रखा जाएगा, और

(ख) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा,

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(4) राज्य सरकार, अधिमूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु यह कि वह व्यक्ति जिसने किसी भी नगरपालिका के सदस्य का चुनाव लड़ा और हारा है, वह सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003 के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नामनिर्देशित सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा-14 की उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित नगरपालिका की अवधि से परे नहीं ।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट नाम निर्देशित सदस्यों तथा नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यपालक अधिकारी के और नगर पंचायत की दशा में मजिस्ट्रेट की नगरपालिका की बैठकों में उपस्थित होने तथा बिना-विमर्श में भाग लेने का अधिकार हो परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

धारा 13

का संशोधन। जायगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 में, विद्यमान उप-धारा (2) का जोड़ किया

बिष्णु सदाशिव कोकजे,  
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला : — — — — —  
तारीख 24 मई, 2003.

— — —

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**H. P. Ordinance No. 4 of 2003.**

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2003**

*Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India.*

AN

**ORDINANCE**

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).*

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

(13 of 1994)

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2003.

Short title

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),—

Amendment of section 10.

(i) in sub-section (3),—

(a) for the words and signs “and the State Government may, by notification, also nominate as members, not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration:”, the sign (.) shall be substituted; and

(b) the existing proviso shall be deleted;

(ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:—

“(4) The State Government may, by notification, nominate as members not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal administration :

Provided that the person who contested and lost the election of any municipality shall not be eligible for nomination as a member :

Provided further that a member nominated under this sub-section whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of Municipality as provided for in sub-section (1) of section 14 of this Act.

(5) The nominated members referred to in sub-section (4) and the Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in case of Nagar Panchayat, shall have right to attend all the meetings of the municipality and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote."

Amendment  
of section  
13.

3. In section 13 of the principal Act, the existing sub-section (2) shall be deleted.